



ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता की स्थिति

डॉ. सिंह अरुण कुमार लक्ष्मण

असि. प्रोफेसर-समाजशास्त्र

काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ज्ञानपुर, भदोही

शोध सार

इक्कीसवीं सदी के तीसरे दशक में भारत एक अभूतपूर्व डिजिटल परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, जिसकी रीढ़ है दूरसंचार क्रांति और बढ़ती इंटरनेट पहुंच। इस परिवर्तन की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण पैमाना यह नहीं है कि कितने गांव ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ गए हैं या कितने सस्ते स्मार्टफोन बिक गए हैं, बल्कि यह है कि ग्रामीण भारत का साधारण नागरिक इन तकनीकों का उपयोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए किस हद तक कर पा रहा है। यहीं पर डिजिटल साक्षरता की अवधारणा केंद्र में आती है। डिजिटल साक्षरता केवल स्मार्टफोन चलाने या व्हाट्सएप संदेश भेजने का कौशल नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक क्षमता है जिसमें सूचना को खोजने, समझने, मूल्यांकन करने, साझा करने और सृजित करने के लिए डिजिटल उपकरणों का सुरक्षित, आलोचनात्मक और रचनात्मक उपयोग शामिल है। यह ई-गवर्नेंस सेवाओं का लाभ उठाने, डिजिटल भुगतान करने, ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करने, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने और अपने उत्पादों के लिए बाजार खोजने जैसी गतिविधियों को संभव बनाती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है क्योंकि यह भौगोलिक दूरियों, भाषाई विविधताओं और सेवाओं की सीमित उपलब्धता जैसी चुनौतियों को पाटने का काम करती है। आज जब सरकारी योजनाओं का लाभ, राशन की उपलब्धता, किसानों को मिलने वाली सब्सिडी, और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत मजदूरी भी डिजिटल माध्यमों से ही सुनिश्चित की जा रही है, ऐसे में डिजिटल निरक्षरता एक नए प्रकार के बहिष्कार का कारण बन सकती है। संसद में हाल ही में उठाए गए सवाल में इस बात को रेखांकित किया गया है कि हजारों मनरेगा मजदूर स्मार्टफोन, इंटरनेट कनेक्टिविटी या बुनियादी डिजिटल साक्षरता के अभाव में अपना पंजीकरण कराने या अपने अधिकारों तक पहुंच बनाने में असमर्थ हैं। यह स्थिति स्पष्ट करती है कि डिजिटल साक्षरता अब एक वैकल्पिक कौशल न रहकर नागरिक अधिकारों और सामाजिक-आर्थिक समावेशन का एक अनिवार्य आधार बन चुकी है। इसलिए, ग्रामीण भारत में

डिजिटल साक्षरता की स्थिति का गहन विश्लेषण न केवल तकनीकी प्रगति का आकलन है, बल्कि यह जांच है कि हम एक समावेशी और सशक्त 'डिजिटल भारत' के निर्माण में कितना सफल हो रहे हैं।

मुख्य शब्द : डिजिटल साक्षरता, मनरेगा, स्मार्टफोन, आईटी मंत्रालय, ई-गवर्नेंस, ऑनलाइन, इन्टरनेट

बुनियादी ढांचे का विस्तार : रीढ़ की हड्डी का निर्माण

किसी भी डिजिटल साक्षरता अभियान की सफलता के लिए सबसे पहली शर्त है मजबूत और विश्वसनीय डिजिटल बुनियादी ढांचे की उपलब्धता। भारत सरकार ने इस दिशा में कई महत्वाकांक्षी परियोजनाएं शुरू की हैं, जिनका उद्देश्य देश के सुदूरतम गांवों तक हाई-स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाना है। इनमें सबसे प्रमुख है भारतनेट परियोजना, जिसे चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जा रहा है ताकि देश के सभी ग्राम पंचायतों और गांवों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जा सके। 4 अगस्त 2023 को सरकार द्वारा अनुमोदित संशोधित भारतनेट कार्यक्रम (एबीपी) वर्तमान में कार्यान्वयन के अधीन है, जिसके तहत भारतनेट चरण-I और चरण-II के मौजूदा नेटवर्क के उन्नयन, शेष ग्राम पंचायतों में नेटवर्क निर्माण और संबंधित ग्राम पंचायतों से शेष ग्रामीण क्षेत्रों को मांग के आधार पर जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, देश के दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों के असंबद्ध गांवों में मोबाइल सेवाएं प्रदान करने के लिए 4जी सैचुरेशन और अन्य मोबाइल परियोजनाएं भी कार्यान्वित की जा रही हैं।

भारतनेट जैसी भूमि-आधारित परियोजनाओं के अलावा, सरकार ने भौगोलिक रूप से पृथक क्षेत्रों को जोड़ने के लिए समुद्री परियोजनाओं पर भी ध्यान केंद्रित किया है। चेन्नई और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के बीच 2312 किलोमीटर लंबी और मुख्य भूमि (कोच्चि) और लक्षद्वीप द्वीप समूह के बीच 1869 किलोमीटर लंबी पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल परियोजनाओं का सफलतापूर्वक कमीशनिंग इस दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। ये परियोजनाएं सुनिश्चित करती हैं कि देश के सबसे दूरस्थ द्वीप क्षेत्र भी डिजिटल मुख्यधारा से न जुड़े रहें। इसके साथ ही, सरकार ने भविष्य की तैयारी भी शुरू कर दी है। मार्च 2023 में भारत 6जी विजन दस्तावेज जारी किया गया, जिसका उद्देश्य 2030 तक भारत को 6जी प्रौद्योगिकी में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने के लिए ऐसी नेटवर्क प्रौद्योगिकियों को डिजाइन, विकसित और परिनियोजित करना है जो दुनिया के लिए उच्च गुणवत्ता वाले जीवन अनुभव के लिए सर्वव्यापी बुद्धिमान और सुरक्षित कनेक्टिविटी प्रदान करें।

हालाँकि, केवल बुनियादी ढांचे का निर्माण ही पर्याप्त नहीं है। संसद में उठाए गए सवालों से पता चलता है कि देश भर के कई शैक्षणिक संस्थानों में अभी भी पर्याप्त डिजिटल बुनियादी ढांचे का अभाव है, जिससे ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों के छात्र आधुनिक शिक्षण उपकरणों और ऑनलाइन शिक्षा संसाधनों से वंचित रह जाते हैं। यह तथ्य इस ओर इशारा करता है कि डिजिटल इंडिया जैसी पहलों के बावजूद, अवसंरचनात्मक अंतराल अभी भी एक विकराल चुनौती है। यह अंतराल केवल ग्रामीण-शहरी विभाजन तक सीमित नहीं है, बल्कि आदिवासी बहुल

और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में यह और भी गहरा है। नैसकॉम फाउंडेशन की सीईओ ज्योति शर्मा के अनुसार, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की आबादी स्मार्टफोन और डिजिटल बुनियादी ढांचे तक सीमित पहुंच के कारण बुनियादी डिजिटल पहचान सेवाओं और आधार-सक्षम लाभों तक भी पहुंच नहीं बना पाती है। इसलिए, बुनियादी ढांचे के विकास के साथ-साथ यह सुनिश्चित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि यह बुनियादी ढांचा वास्तव में अंतिम छोर तक पहुंचे और सभी वर्गों के लिए सुलभ हो।

राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन : प्रगति और चुनौतियां

बुनियादी ढांचे के विकास के समानांतर, सरकार ने ग्रामीण आबादी को डिजिटल रूप से साक्षर बनाने के लिए कई प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू किए हैं। इनमें सबसे महत्वाकांक्षी है प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीडीआईएसएचए), जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (मीतवाई) के तहत राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के सक्रिय सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए कार्यान्वित किया गया है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों के कम से कम एक सदस्य को डिजिटल रूप से साक्षर बनाना है, ताकि वे कंप्यूटर या मोबाइल उपकरणों का उपयोग करके सूचना का आदान-प्रदान कर सकें, ई-मेल भेज और प्राप्त कर सकें, और सरकारी सेवाओं का ऑनलाइन लाभ उठा सकें।

पीएमजीडीआईएसएचए जैसे कार्यक्रमों के अलावा, सरकार अब उभरती प्रौद्योगिकियों में कौशल विकास पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। महत्वाकांक्षी इंडिया एआई मिशन के तहत, सरकार ने कॉमन सर्विसेज सेंटर के तहत 5.5 लाख ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई) को मुफ्त कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रशिक्षण प्रदान करने की राष्ट्रव्यापी पहल की घोषणा की है। यह पहल इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के सहयोग से शुरू की गई है और इसका उद्देश्य भारत के ग्रामीण कार्यबल को कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स, साइबर सुरक्षा, क्लाउड कंप्यूटिंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे अत्याधुनिक डोमेन में प्रशिक्षित करना है। इस कार्यक्रम के तहत, ग्रामीण उद्यमी न केवल डिजिटल रूप से साक्षर होंगे, बल्कि वे अपने समुदायों के लिए एआई-संचालित समाधान विकसित करने और तैनात करने में सक्षम होंगे, जैसे कि एआई-आधारित फसल पूर्वानुमान, स्थानीय मौसम पूर्वानुमान, स्मार्ट हेल्थकेयर और टेलीमेडिसिन सेवाएं।

महिलाओं के डिजिटल सशक्तीकरण पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मई 2025 में प्यशोदा एआई नामक एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता साक्षरता पहल शुरू की, जिसके तहत अब तक लगभग 2,500 ग्रामीण और अर्ध-शहरी महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। यह कार्यक्रम महिलाओं को एआई साक्षरता, साइबर सुरक्षा, डिजिटल गोपनीयता और सुरक्षित ऑनलाइन प्रथाओं की समझ से लैस करके डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देना है। प्रशिक्षण में स्वयं सहायता समूहों की सदस्यों, सरपंचों, प्रधानों, पार्षदों, आशा कार्यकर्ताओं, लघु-उद्यमियों, शिक्षकों और छात्रों सहित महिलाओं के एक विविध समूह को शामिल किया गया है

। यह पहल प्रौद्योगिकी जागरूकता और उपयोग में लैंगिक अंतर को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

हालाँकि, इन प्रयासों के बावजूद, चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26 के अनुसार, अब मुख्य चुनौती केवल कनेक्टिविटी और हार्डवेयर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि कनेक्टिविटी का उपयोग सार्थक शिक्षा और उत्पादक गतिविधियों के लिए हो। सर्वेक्षण में पाया गया कि लगभग तीन-चौथाई ग्रामीण युवा मुख्य रूप से सोशल मीडिया के लिए स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं, जो डिजिटल उपकरणों के उपयोग के असंतुलन को दर्शाता है। यह एक नई नीतिगत चुनौती पैदा करता है – केवल प्रशिक्षण प्रदान करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि प्रशिक्षण का परिणाम वास्तविक जीवन में उत्पादक उपयोग के रूप में दिखे। इसके अलावा, डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों की पहुंच और प्रभावशीलता को लेकर भी सवाल उठते हैं, विशेषकर सबसे हाशिए के समुदायों, जैसे कि विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों तक, जहां साक्षरता दर स्वयं राष्ट्रीय औसत से काफी कम है।

लैंगिक डिजिटल विभाजन : महिलाओं का पिछड़ना

ग्रामीण भारत में डिजिटल साक्षरता की स्थिति का विश्लेषण करते समय लैंगिक आयाम सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। जहां एक ओर सरकारी आंकड़े बताते हैं कि भारत में 55% से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता ग्रामीण क्षेत्रों से हैं, वहीं दूसरी ओर दैनिक इंटरनेट उपयोग के मामले में शहरी उपयोगकर्ता अभी भी ग्रामीण उपयोगकर्ताओं से आगे हैं। यह अंतर केवल भौगोलिक नहीं है, बल्कि इसमें लैंगिक आयाम भी गहराई से शामिल है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की डिजिटल पहुंच और साक्षरता पुरुषों की तुलना में काफी कम है, जो एक व्यापक सामाजिक-आर्थिक असमानता का प्रतिबिंब है। नैसकॉम फाउंडेशन की रिपोर्ट के अनुसार, महिलाओं और जनजातीय आबादी के लिए डिजिटल बहिष्कार सिर्फ स्मार्ट डिवाइस की कमी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आवश्यक सेवाओं और अवसरों से एक गहरा वियोग पैदा करता है।

ग्रामीण महिलाओं के डिजिटल बहिष्कार के कई कारण हैं। सबसे पहले, सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाएं महिलाओं की तकनीक तक पहुंच को सीमित करती हैं। कई ग्रामीण परिवारों में, स्मार्टफोन को पुरुषों का साधन माना जाता है, और महिलाओं के लिए मोबाइल फोन का उपयोग करना या इंटरनेट पर सर्फिंग करना सामाजिक रूप से स्वीकार्य नहीं है। दूसरे, आर्थिक बाधाएं भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सीमित पारिवारिक संसाधनों में, प्राथमिकता अक्सर पुरुष सदस्यों के लिए स्मार्टफोन खरीदने की होती है। तीसरे, शैक्षिक असमानताएं भी डिजिटल विभाजन को गहरा करती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला साक्षरता दर पुरुषों की तुलना में कम है, जो डिजिटल साक्षरता हासिल करने की उनकी क्षमता को सीधे प्रभावित करती है। आदिवासी समुदायों में तो यह स्थिति और

भी विकट है, जहां विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों में साक्षरता दर मात्र 47.7% है, जो राष्ट्रीय औसत 77.3% से काफी कम है ।

इन चुनौतियों के बावजूद, कुछ सकारात्मक पहल भी देखने को मिल रही हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की श्यशोदा एआईश पहल ने 2,500 से अधिक ग्रामीण और अर्ध-शहरी महिलाओं को प्रशिक्षित किया है, जिसमें स्वयं सहायता समूहों की सदस्य, सरपंच, प्रधान, पार्षद, आशा कार्यकर्ता, लघु-उद्यमी शामिल हैं । इसी तरह, इंडिया एआई मिशन के तहत ग्राम स्तरीय उद्यमियों को दिए जा रहे प्रशिक्षण में महिलाओं और हाशिए के समुदायों पर विशेष जोर दिया गया है । ये पहलें डिजिटल साक्षरता को केवल एक कौशल के रूप में नहीं, बल्कि महिला सशक्तीकरण के एक साधन के रूप में देखती हैं। जब महिलाएं डिजिटल रूप से साक्षर हो जाती हैं, तो वे न केवल सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकती हैं, बल्कि वे डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन व्यवसाय और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से आर्थिक रूप से स्वतंत्र भी बन सकती हैं ।

आदिवासी और सुदूरवर्ती समुदायों की विशिष्ट चुनौतियां

ग्रामीण भारत की डिजिटल साक्षरता कहानी में आदिवासी और सुदूरवर्ती समुदाय सबसे कमजोर कड़ी हैं। देश की कुल जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होने के बावजूद, ये समुदाय डिजिटल क्रांति के लाभों से काफी हद तक अछूते रहे हैं। नैसकॉम फाउंडेशन की सीईओ ज्योति शर्मा के अनुसार, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी), जिनकी आबादी 44,71,005 है, भारत के सबसे हाशिए के समुदायों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये समूह पूर्व-कृषि अर्थव्यवस्थाओं, स्थिर साक्षरता दर और मुख्यधारा के विकास के अवसरों तक न्यूनतम पहुंच से चिह्नित हैं ।

इन समुदायों के सामने चुनौतियां बहुआयामी हैं। सबसे पहली और सबसे बुनियादी चुनौती है भौगोलिक दुर्गमता। ये समुदाय अक्सर घने जंगलों, पहाड़ियों या द्वीपों जैसे दूरदराज के क्षेत्रों में निवास करते हैं, जहां मोबाइल टावर और ब्रॉडबैंड कनेक्शन जैसी बुनियादी दूरसंचार सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। सरकार ने अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप के लिए पनडुब्बी केबल परियोजनाएं शुरू की हैं, लेकिन मुख्य भूमि के कई सुदूरवर्ती आदिवासी क्षेत्र अभी भी कनेक्टिविटी से वंचित हैं । दूसरी चुनौती है भाषाई बाधा। अधिकांश डिजिटल सामग्री और प्रशिक्षण कार्यक्रम हिंदी या अंग्रेजी में हैं, जबकि आदिवासी समुदायों की अपनी अलग भाषाएं और बोलियां हैं। तीसरी चुनौती है सांस्कृतिक अलगाव। इन समुदायों का आधुनिक तकनीक से बहुत कम परिचय है, और बाहरी दुनिया के प्रति एक स्वाभाविक अविश्वास भी है।

तीसरी और सबसे गंभीर चुनौती है निम्न साक्षरता स्तर। जब बुनियादी साक्षरता ही एक चुनौती है, तो डिजिटल साक्षरता एक और भी दूर का लक्ष्य बन जाती है। ट्राइबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 के अनुसार, पीवीटीजी के बीच साक्षरता दर मात्र 47.7% है, जो राष्ट्रीय औसत 77.3% से काफी कम है । यह आंकड़ा बताता है कि

इन समुदायों के लिए डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए, पहले बुनियादी साक्षरता पर ध्यान देना होगा। नैसकॉम फाउंडेशन ने सुझाव दिया है कि इसके लिए एक अति-स्थानीय, सांस्कृतिक रूप से अनुकूलित दृष्टिकोण की आवश्यकता है। प्रशिक्षण मॉड्यूल को स्थानीय भाषाओं में डिजाइन किया जाना चाहिए, जिसमें दृश्य और ऑडियो सहायता शामिल हो। इससे भी महत्वपूर्ण बात, इन्हीं समुदायों के भीतर से डिजिटल राजदूतों का निर्माण किया जाना चाहिए जो डिजिटल साक्षरता को अपनाने में परिवर्तनकारी भूमिका निभा सकते हैं।

सरकार ने इस दिशा में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू किया है, जो जमीनी स्तर पर डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए एक लक्षित हस्तक्षेप है। यह कार्यक्रम आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता पर आधारित है और भारत के सबसे वंचित क्षेत्रों, विशेष रूप से महत्वपूर्ण जनजातीय आबादी वाले क्षेत्रों, के केंद्रित सशक्तीकरण को सक्षम बनाता है। यह कार्यक्रम डिजिटल संसाधनों और ई-गवर्नेंस सेवाओं को अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए प्रौद्योगिकी-सक्षम शिक्षा को भौतिक बुनियादी ढांचे और सामुदायिक जुड़ाव के साथ जोड़ता है।

डिजिटल साक्षरता का विरोधाभास : उपयोग बनाम दुरुपयोग

ग्रामीण भारत में डिजिटल साक्षरता के विस्तार के साथ एक नया विरोधाभास सामने आया है – डिजिटल उपकरणों तक पहुंच का बढ़ना जरूरी नहीं कि सार्थक डिजिटल उपयोग में तब्दील हो रहा हो। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 ने इस ओर स्पष्ट रूप से इशारा किया है, जिसमें बताया गया है कि 14 से 16 वर्ष के 89.1% ग्रामीण किशोरों के पास घर पर स्मार्टफोन की पहुंच है। यह पिछले वर्षों की तुलना में एक बड़ा बदलाव है, जब डिवाइस की उपलब्धता और इंटरनेट की लागत डिजिटल शिक्षा में मुख्य बाधाएं हुआ करती थीं। आज, स्मार्टफोन ग्रामीण परिवारों में व्यापक रूप से फैल गए हैं, जिसने मौलिक रूप से बदल दिया है कि युवा लोग कैसे संवाद करते हैं, सामग्री का उपभोग करते हैं, और ऑनलाइन समय बिताते हैं।

हालाँकि, सर्वेक्षण में पाया गया कि लगभग तीन-चौथाई ग्रामीण युवा मुख्य रूप से सोशल मीडिया, मनोरंजन और लघु-अवधि सामग्री के लिए स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं। जबकि आधे से अधिक ग्रामीण उपयोगकर्ता शैक्षिक उद्देश्यों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं, सोशल मीडिया प्रमुख गतिविधि बना हुआ है। यह असंतुलन डिजिटल उपकरणों की शैक्षणिक सहभागिता और कौशल विकास में सुधार की क्षमता को सीमित करता है, और संभावित रूप से डिजिटल लक्ष्य का कारण बन सकता है। यह एक वैश्विक नीतिगत प्रश्न है, और भारत इस चुनौती से अकेले नहीं जूझ रहा है। ऑस्ट्रेलिया, चीन, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों ने युवाओं को डिजिटल नुकसान से बचाने के लिए आयु-आधारित प्रतिबंध और नियम पेश किए हैं।

इस विरोधाभास से निपटने के लिए, आर्थिक सर्वेक्षण ने सुझाव दिया है कि डिजिटल शिक्षा नीति का ध्यान अब कनेक्टिविटी से हटकर क्षमता निर्माण पर केंद्रित होना चाहिए। सरकार निम्नलिखित उपाय प्रस्तावित कर रही है: डिजिटल वेलनेस पाठ्यक्रम, जिसमें स्कूलों में फ्लैग-टाइम साक्षरता सिखाई जाए; छोटे बच्चों के लिए

केवल शिक्षा—उद्देश्य वाले टैबलेट या बेसिक फोन को बढ़ावा देना; और शारीरिक संपर्क को प्रोत्साहित करने और रात में देर तक स्कॉल करने से होने वाली ज्नींद की कमीष को कम करने के लिए “यूथ हब” की स्थापना करना ।

इसी तरह की चिंता साइबर सुरक्षा को लेकर भी है। संसद में उठाए गए सवालोंने, राज्यसभा सांसदोंने तेजी से बढ़ते साइबर सुरक्षा खतरों और साइबर हमलों पर चिंता व्यक्त की। बैंकिंग, सरकारी डेटाबेस और बुनियादी ढांचे सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कमजोरियों को रेखांकित किया गया। सरकार ने टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 और भारतीय न्याय संहिता 2023 में डेटा उल्लंघन रिपोर्टिंग, डेटा संरक्षण, दंड आदि को अनिवार्य करते हुए पर्याप्त कानूनी और तकनीकी उपाय किए हैं। लेकिन इन कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन और आम नागरिकों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के नव-डिजिटल साक्षर नागरिकों तक साइबर सुरक्षा जागरूकता पहुंचाना, एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।

सफलता की कहानियां : केरल का डिजिटल साक्षरता मॉडल

राष्ट्रीय स्तर पर चुनौतियों के बीच, कुछ राज्यों ने डिजिटल साक्षरता के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है, जो पूरे देश के लिए एक मॉडल प्रस्तुत करती है। इनमें सबसे प्रमुख है केरल, जो अगस्त 2025 में भारत का पहला राज्य बन गया जहां 100% डिजिटल साक्षरता हासिल की गई। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने आधिकारिक घोषणा की कि राज्य सरकार के डिजिटल केरल डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम के तहत 21.87 लाख लोगों ने प्रशिक्षण पूरा किया। यह उपलब्धि 1980 के दशक के उत्तरार्ध के ऐतिहासिक संपूर्ण साक्षरता अभियान की याद दिलाती है, जब केरल ने साक्षरता के क्षेत्र में देश का नेतृत्व किया था।

केरल की सफलता की कहानी 2021 में तिरुवनंतपुरम से लगभग 25 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी ग्रामीण क्षेत्र पुल्लमपारा से शुरू होती है। पंचायत में कुछ बैंकों के सामने नियमित रूप से लंबी कतारें देखी गईं, जिनमें से कई मनरेगा मजदूर थे, जो केवल अपना खाता शेष देखने के लिए लंबी दूरी तय करके आते थे। तत्कालीन जिला महिला कल्याण अधिकारी सजीना सथार और स्थानीय स्वशासन विभाग के अन्य अधिकारियों ने इन मजदूरों की दुर्दशा को देखा और उन्हें दैनिक जीवन में आवश्यक बुनियादी डिजिटल तकनीक सिखाने के बारे में सोचा। इस तरह ‘डिजिटल पुल्लमपारा’ परियोजना का जन्म हुआ, जो बाद में डिजिटल केरल का अग्रदूत बनी।

पंचायत अध्यक्ष पी.वी. राजेश के नेतृत्व में पांच सदस्यीय कोर टीम ने अगस्त 2021 में पंचायत के सभी निवासियों को डिजिटल साक्षरता प्रदान करने की योजना शुरू की। सभी वार्डों में डिजिटल रूप से निरक्षर व्यक्तियों की पहचान के लिए एक सर्वेक्षण किया गया। इस प्रकार पहचाने गए 3,917 लोगों में से 3,300 को प्रशिक्षण प्रदान किया गया, शेष बिस्तर पर पड़े मरीज थे। केरल की सफलता के कई कारण हैं। पहला, राज्य की मजबूत स्थानीय स्वशासन प्रणाली, जिसने डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए जमीनी स्तर पर प्रभावी

कार्यान्वयन सुनिश्चित किया। दूसरा, उच्च मानव विकास सूचकांक और बुनियादी साक्षरता दर, जिसने डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों के लिए एक अनुकूल वातावरण प्रदान किया। तीसरा, राजनीतिक इच्छाशक्ति और नौकरशाही की प्रतिबद्धता, जिसने इस अभियान को एक जनांदोलन का रूप दिया। केरल का यह मॉडल बताता है कि यदि सही रणनीति और सामुदायिक भागीदारी हो, तो डिजिटल साक्षरता का लक्ष्य असंभव नहीं है। यह अन्य राज्यों के लिए एक प्रेरणा है कि कैसे स्थानीय संसाधनों और सामुदायिक नेतृत्व का उपयोग करके राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है।

भविष्य की रणनीति : सार्वजनिक-निजी भागीदारी से लेकर सतत मूल्यांकन तक

ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक बहुआयामी रणनीति की आवश्यकता है, जिसमें केवल सरकारी प्रयास ही नहीं, बल्कि निजी क्षेत्र, गैर-सरकारी संगठन और सामुदायिक संस्थानों की सक्रिय भागीदारी भी शामिल हो। सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) इस दिशा में एक महत्वपूर्ण मॉडल के रूप में उभर रही है। कॉमन सर्विसेज सेंटर (सीएससी) इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जो पीपीपी मॉडल पर स्थापित किए गए हैं और नागरिकों को सरकारी, निजी और सामाजिक क्षेत्र की सेवाएं प्रदान करने वाले फ्रंट-एंड डिलीवरी पॉइंट के रूप में कार्य करते हैं। आज 5 लाख से अधिक सक्रिय केंद्रों के साथ, सीएससी नेटवर्क देश के सबसे दूरस्थ भागों में सरकारी सेवाओं, डिजिटल शिक्षा और वित्तीय समावेशन पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

सेत्रिसा टेक्नोलॉजीज जैसी निजी कंपनियां भी डिजिटल समावेशन में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। पिछले एक दशक में, सेत्रिसा ने 3 करोड़ से अधिक ग्रामीण लोगों के जीवन को बदल दिया है, जो एआई-संचालित, भारत-प्रथम डिजिटल समाधान प्रदान कर रही है। कंपनी ने कम कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में काम करने वाले इंफ्रा-लाइट प्लेटफॉर्म विकसित किए हैं, जो ग्रामीण भारत की वास्तविकताओं के अनुरूप डिजाइन किए गए हैं। उदाहरण के लिए, उनका उत्पाद बिजुआई बिना जीपीयू के और कम-बैंडविड्थ वाले ग्रामीण क्षेत्रों में वास्तविक समय निगरानी प्रदान करता है। इसी तरह, उनका प्लेटफॉर्म उनिजैप एमएसएमई और लघु-उद्यमियों के लिए बनाया गया है, जो मोबाइल-फ्रेंडली और स्थानीय भाषा-समर्थ है, जिसमें एआई-संचालित कैंटलॉग बिल्डर, क्यूआर-आधारित ऑनबोर्डिंग और वन-क्लिक ओएनडीसी एकीकरण जैसी सुविधाएं हैं।

भविष्य की रणनीति में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहलों की भी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। नैसकॉम फाउंडेशन के अनुसार, सीएसआर पहलों को सरकारी कार्यक्रमों के पूरक के रूप में डिजिटल कौशल को एकीकृत करना चाहिए। प्रभाव को मापने के लिए, रोजगार दरों, उद्यमशीलता वृद्धि और डिजिटल अपनाने की निगरानी करने वाले मूल्यांकन ढांचे को लागू करना महत्वपूर्ण है। आर्थिक सर्वेक्षण ने भी डिजिटल शिक्षा नीति का ध्यान कनेक्टिविटी से हटाकर क्षमता निर्माण पर केंद्रित करने का सुझाव दिया है। इसके लिए, स्कूलों में

“डिजिटल वेलनेस पाठ्यक्रम” शुरू करना, केवल शिक्षा-उद्देश्य वाले टैबलेट को बढ़ावा देना और युवाओं के लिए ऑफलाइन विकल्प के रूप में प्यूथ हब स्थापित करना जैसे उपाय प्रस्तावित हैं ।

डिजिटल साक्षरता का लक्ष्य केवल एक कौशल सिखाना नहीं है, बल्कि व्यक्तियों को सशक्त बनाना है ताकि वे डिजिटल अर्थव्यवस्था में सक्रिय भागीदार बन सकें। जैसा कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, “यह केवल एक कौशल पहल नहीं है। यह हमारे ग्रामीण उद्यमियों को ऐसे उपकरणों के साथ सशक्त बनाने का मिशन है जो उन्हें सम्मान और स्वायत्तता के साथ भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था में भाग लेने में सक्षम बनाते हैं। एआई मेट्रो-शहर का विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए। हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि यह गांव की ताकत बने”।

निष्कर्ष

ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता की स्थिति का यह व्यापक विश्लेषण बताता है कि भारत एक ऐतिहासिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। एक ओर, भारतनेट जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाएं देश के सुदूरतम गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ रही हैं, तो दूसरी ओर, पीएमजीडीआईएसएचए और इंडिया एआई मिशन जैसे कार्यक्रम ग्रामीण आबादी को डिजिटल रूप से साक्षर बना रहे हैं । स्मार्टफोन की पहुंच अब ग्रामीण परिवारों में व्यापक हो गई है, और 14-16 वर्ष के 89.1% ग्रामीण किशोरों के पास घर पर स्मार्टफोन की उपलब्धता है । यह आंकड़ा पिछले वर्षों की तुलना में एक बड़ी उपलब्धि है ।

हालाँकि, इस सफलता की कहानी के साथ-साथ कई चुनौतियाँ भी सामने आई हैं। पहली चुनौती है उपयोग बनाम दुरुपयोग का विरोधाभास। लगभग तीन-चौथाई ग्रामीण युवा मुख्य रूप से सोशल मीडिया और मनोरंजन के लिए स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं, न कि शैक्षिक या उत्पादक गतिविधियों के लिए । दूसरी चुनौती है लैंगिक डिजिटल विभाजन। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की डिजिटल पहुंच और साक्षरता पुरुषों की तुलना में काफी कम है । तीसरी चुनौती है आदिवासी और सुदूरवर्ती समुदायों तक पहुंच, जहां भौगोलिक दुर्गमता, भाषाई बाधाएं और निम्न साक्षरता स्तर डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन में बाधा डालते हैं । चौथी चुनौती है साइबर सुरक्षा, जहां डिजिटल रूप से नए साक्षर नागरिक साइबर अपराधों के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकते हैं ।

इन चुनौतियों का समाधान एक बहुआयामी दृष्टिकोण से ही संभव है। केरल का मॉडल बताता है कि मजबूत स्थानीय स्वशासन, उच्च बुनियादी साक्षरता और राजनीतिक इच्छाशक्ति से डिजिटल साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। सार्वजनिक-निजी भागीदारी, जैसे कि सीएससी और सेत्रिसा जैसी कंपनियों की पहल, डिजिटल समावेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। सीएसआर पहल और गैर-सरकारी संगठन भी इस मिशन में योगदान दे सकते हैं। नीतिगत स्तर पर, डिजिटल शिक्षा का ध्यान केवल कनेक्टिविटी से हटकर क्षमता निर्माण और सार्थक उपयोग पर केंद्रित होना चाहिए ।

2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, यह अनिवार्य है कि भारत के सबसे कमजोर समुदायों को डिजिटल दायरे में लाया जाए। डिजिटल साक्षरता आर्थिक सशक्तीकरण और सामाजिक समावेशन के चौराहे पर खड़ी है, जो भारत की विकास कहानी में एक निर्णायक क्षण का प्रतिनिधित्व करती है। सार्वजनिक-निजी भागीदारी और स्केलेबल, प्रौद्योगिकी-संचालित समाधानों के माध्यम से हमारा सामूहिक कार्य यह निर्धारित करेगा कि हम इस विभाजन को कितनी प्रभावी ढंग से पाटते हैं। डिजिटल समावेशन को अभी प्राथमिकता देकर, हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि भारत के सबसे कमजोर समुदाय न केवल हमारे राष्ट्र के तकनीकी और आर्थिक भविष्य में भाग लें, बल्कि सक्रिय रूप से इसे आकार भी दें।

सन्दर्भ सूची

- सेतिया सुभाष (2012) – गाँवों में सूचना प्रौद्योगिकी का बढ़ता प्रभाव, कुरुक्षेत्र ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली।
- कुमार विरेन्द्र (2017) – ई-तकनीकी का ग्रामीण विकास में योगदान कुरुक्षेत्र सूचना प्रशासन मंत्रालय, नई दिल्ली।
- मित्तल संजीव (2013) – कुरुक्षेत्र सूचना प्रशासन मंत्रालय, नई दिल्ली।
- सिंह, नीना (2007) – भारत में डिजिटल विभाजन को पाटना : चुनौतियाँ और अवसर, विश्व पुस्तकालय, खंड 17
- शीतल टी. एवं जी. कृष्णमूर्ति (2013) – कैशलेस ग्रामीण अर्थव्यवस्था – एक सपना या हकीकत? झारखंड जर्नल ऑफ डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट स्टडीज एक्स,आई,एस.एस. रांची (झारखंड)।
- योति यादव (2015) – डिजिटल इंडिया : ग्रामीण भारत के विकास के लिए एक रोडमैप, 'टरनेशनल जर्नल ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट रिसर्च', आईएसएसएन 2455-1627।
- जिंदल एस और ओझा बनाम (2017) – ई-पंचायत : एक क्रांति, 'टरनेशनल जर्नल ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, खंड